International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11 Issue 01, January- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|

भारत में प्राथमिक शिक्षा में रुझान का अध्ययन

Krishna Kumar Srivastav, Research Scholar, Dept of Education, Himalayan Garhwal University, Uttarakhand

Dr Vinita Vashishtha, Professor, Dept of Education, Himalayan Garhwal University, Uttarakhand

सारांश

भारत की शिक्षा प्रणाली आज बड़े पैमाने पर अपने अतीत का परिणाम है। सभी देशों की वृद्धि और समृद्धि उनकी मजबूत शिक्षा प्रणाली पर निर्भर है। पिछले एक दशक में, भारत ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में काफी प्रगति की है। प्राथमिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का प्रमुख चरण है। गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच पढ़ने, लिखने और अंकगणित के बारे में बुनियादी ज्ञान को प्रशिक्षित करना है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता किसी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार इसमें एक राष्ट्र के मानव संसाधनों को विकसित करने की क्षमता है। एक बच्चे को प्राप्त प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा उसके भविष्य के जीवन स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1994 में, जिला शिक्षा पुनरोद्धार कार्यक्रम (डीईआरपी) शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। मुख्य ध्यान प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार पर था। सदियों से, भारत सीखने के लिए एक प्रमुख केंद्र रहा है और कई लोकप्रिय विश्वविद्यालय यहां रहे हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली जल्द ही शत–प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के अब तक के अप्राप्य सपने को साकार करेगी। 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के कुल नामांकन के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना और प्राथमिक चरण पूरा करने तक उन्हें बनाए रखना निरक्षरता को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की उच्च दर और अपव्यय और कम नामांकन दर इस निराशाजनक प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार प्रतीत होती है। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (ओबीबी), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) आदि जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए ।

कुंजी शब्द : भारत, महिला, शिक्षा, विकास, महत्वपूर्ण, भूमिका.

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11Issue 01, January- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|

परिचय

भारत में प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान संरचना में 8 साल की शिक्षा शामिल है। यानी, 5 साल की प्राथमिक शिक्षा और 3 साल की उच्च प्राथमिक शिक्षा।

भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

देश में महिलाओं की शिक्षा के मुद्दे की स्वतंत्रता के बाद से कई समितियों और आयोगों द्वारा समीक्षा और विश्लेषण किया गया है।

साक्षरता में व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने ज्ञान और क्षमता को विकसित करने और अपने समुदाय और समाज में पूरी तरह स भाग लेने में सक्षम बनाने में सीखने की निरंतरता शामिल है । शिक्षा का अधिकारएक मौलिक अधिकार है और यूनेस्को का लक्ष्य वर्ष 2015 तक सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करना है। व्यक्तियों के लिए साक्षरता के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने हमारे देश की महिलाओं के बीच साक्षरता दर बढ़ाने के लिए समितियों और आयोगों की नियुक्ति की है और नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाया है।

स्कूल शिक्षा का परिचय

पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में वद, पुराण, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र आदि शामिल हैं । गुरुकुल ज्ञान को बढ़ाने वाली प्राचीन भारतीय पद्धति थी। इस प्रणाली में, किशोर लड़कों को एक निर्दिष्ट समय अवधि में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के घर में रखा जाता था। मध्य युग में, गुरुकुल में महिलाओं और निचली जाति के लोगों को अनुमति नहीं थी। उन्नीसवीं शताब्दी में, शैक्षिक सुधारों को महत्व मिला और सूफी, भक्ति, जैन और बौद्ध धर्मों द्वारा सुधार का क्षण फैल गया और समाज के परेशान क्षेत्रों के दर्द को कम किया।

एक राष्ट्र के मानव संसाधनों को विकसित करने की क्षमता, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता किसी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी देश में सामाजिक विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता साक्षर जनसंख्या और सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता को देखते हुए प्रसिद्ध देशभक्त गापाल कृष्ण गोखले ने 1911 में शाही विधान परिषद में सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लेकिन उनका यह प्रयास व्यर्थ हो गया। भारत का संविधान, अनुच्छेद 45 1960 तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। लक्ष्य तिथि को समय–समय पर 1960 से 1970 तक फिर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11Issue 01, January- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|

1976 और बाद में 1990 तक संशोधित किया गया है। कार्यक्रम ऑफ एक्शन (पीओए), 1992 ने लक्ष्य को 2015 ईस्वी तक संशोधित किया जो अभी तक एक लंबा रास्ता तय नहीं कर पाया है।

हालांकि, उपलब्धियों के बावजूद, भारत को बुनियादी सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को साकार करना बाकी है । भारत सरकारने प्रारंभिक शिक्षा को अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बनाने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। चूंकि, स्वतंत्रता के प्रयास प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा जैसी पहलों के साथ साक्षरता दर में सुधार करने की प्रक्रिया में थे। सबके लिए शिक्षा सरकार का मिशन बन गया। शिक्षा में भेदभाव की अस्वास्थ्यकर प्रथा को 86 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था आर शिक्षा ने 6 से 14 आयु वर्ग के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। वर्ष 1953 में, यूजीसी की स्थापना देश में शैक्षिक विकास की प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी।

आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने जो प्रगति की है, वह पूरे एशिया में अभूतपूर्व है। भारत के इतिहास में पहली बार, शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित की गई थी, यानी एक ऐसी प्रणाली जिसका अर्थ है जाति, पंथ या लिंग के बावजूद सभी छात्रों के लिए शिक्षा की पहुंच। यह भी सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। यूनेस्को के महानिदेशक एफ एडेरिको मेयर ने एक बार कहा था, 'शिक्षा न्यायसंगत वातावरण और लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण समाज बनाने की कुंजी है जहां महिलाएं और पुरुष समान रूप से महत्वपूण भूमिका निभाते हैं।

भारत में, स्कूल तीन अलग–अलग प्रकार के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। अर्थात्, कुछ स्कूल राज्य पाठ्यक्रम का पालन कर रहे हैं , कुछ स्कूल केंद्रीय पाठ्यक्रम का पालन कर रहे हैं, और कुछ स्कूल अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम का पालन कर रहे हैं। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों की निगरानी उच्च शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा की जाती है।

अनुसंधान क्रियाविधि

डेटा स्रोतः

माध्यमिक डेटा छात्रों, नियोजित शिक्षकों की कुल संख्या, हर स्तर यानी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूलों की संख्या से संबंधित है और भारत में शिक्षा का वित्तपोषण मंत्रालय से प्राप्त किया गया है। मानव संसाधन विकास योजना, निगरानी और सांख्यिकी

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11Issue 01, January- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|

ब्यूरो नई दिल्ली, स्कूल शिक्षा के सांख्यिकी, एक नज़र में शिक्षा सांख्यिकी, भारत में स्कूल शिक्षा, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, भारत सरकार। भारत में शिक्षा के वित्तपोषण से संबंधित डेटा शिक्षा पर बजट व्यय के विश्लेषण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार से एकत्र किया जाता है ।

डेटा की प्रकृति

अध्ययन पूरी तरह से माध्यमिक डेटा पर आधारित है। द्वितीयक डेटा का अर्थ है, उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्र किया गया डेटा। जनगणना, सरकारी विभागों द्वारा एकत्र की गई जानकारी, मूल रिकॉर्ड और डेटा जो मूल रूप से अन्य शोध के लिए एकत्र किए गए थे , सामाजिक विज्ञान के लिए माध्यमिक डेटा के सामान्य स्रोत हैं।

विश्लेषण की तकनीकः

सारणीबद्ध विश्लेषण तकनीक समय श्रृंखला डेटा का विश्लेषण करने के लिए नियोजित है । और रैखिक प्रवृत्ति समीकरण मौजूदा रुझानों का अनुमान लगाने और चयनित बारह चर में परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी लागू किया जाता ह, और परिवर्तनों की सांख्यिकीय वैधता की जांच करने के लिए "एफ" और "सहसंबंध गुणांक के लिए टी वैलूई" जैसे महत्व के परीक्षण को नियोजित किया जाता है।

पहले उल्लिखित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का उपयोग किया जाता है । अध्ययन सरल उपकरणों जैसे प्रतिशत, वार्षिक वृद्धि दर , चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, औसत वार्षिक वृद्धि दर, रैखिक प्रवृत्ति मूल्य, सहसंबंध, भिन्नता का गुणांक, विचरण का विश्लेषण, लिंग समानता सूचकांक, लिंग अंतर, प्रतिशत लिंग के साथ किया जाता है अन्तर।

डेटा विश्लेषण और व्याख्या

प्राथमिक शिक्षा में छात्र नामांकन में लिंग अंतरः

1991–1992 से 2015–2016 तक भारत में प्राथमिक शिक्षा में छात्र नामांकन की वार्षिक स्थिति की जांच यहां की गई है। डेटा भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किए जाते हैं । प्राथमिक शिक्षा में छात्र नामांकन की स्थिति की जांच तालिका 1 में की गई है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11Issue 01, January- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|

तालिका 1. प्राथमिक शिक्षा में छात्र नामांकन में लिंग अंतर (लाखों में छात्र नामांकन)

साल	लड़कों	लड़कियों	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)
1991 - 1992	58.6	42.3	100.9
1992 - 1993	57.9	41.7	99.6
1993 - 1994	55.1	41.9	97.0
1994 - 1995	60.0	45.1	105.1
1995 - 1996	60.9	46.2	107.1
1996 - 1997	61.4	46.8	108.2
1997 - 1998	62.3	48.0	110.3
1998 - 1999	62.7	49.0	111.7
1999 - 2000	63.6	50.0	113.6
2000 - 2001	64.0	49.8	113.8
2001 - 2002	63.6	50.3	113.9
2002 - 2003	65.1	57.3	122.4
2003 - 2004	68.4	59.9	128.3
2004 - 2005	69.7	61.1	130.8
2005 - 2006	70.5	61.6	132.1
2006 - 2007	71.1	62.6	133.7
2007 - 2008	71.1	64.4	135.5
2008 - 2009	70.6	64.7	135.3
2009 - 2010	69.7	63.9	133.6
2010 - 2011	70.2	64.6	134.8
2011 - 2012	72.7	67.2	139.9
2012 - 2013	69.6	65.2	134.8
2013 - 2014	68.6	63.8	132.4
2014 - 2015	67.6	62.9	130.5
2015 - 2016	66.8	62.3	129.1

स्रोतः भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय योजना, निगरानी और सांख्यिकी ब्यूरो नई दिल्ली 2014। स्कूल शिक्षा के आंकड़े 2011–2012, एस –1, एस –4।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11Issue 01, January- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|

एक नज़र में शिक्षा के आंकड़े – 2014, तालिका – 17, पृष्ठ संख्याः 15। 2012–2013 (पी) और 2013–20 14 (पी) के लिए चित्र यू–डीआईएसईएनयूईपीए से लिया गया है। समानता के साथ गुणवत्ता की ओर सभी के लिए शिक्षा, भारत, तालिका 2.2.1, पृष्ठ संख्या 22। भारत में स्कूल शिक्षा, फ्लैश सांख्यिकी, यू – डीआईएसई 2014 – 2015, तालिका 3.2, पीजी। नहीं। 34.

वर्ष पुस्तिका 2016–2017, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और डीआईएसई, एनयूईपीए (2012–2013 से स्कूल शिक्षा)।

तालिका IV.1 से यह देखा जा सकता है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा में छात्र नामांकन में स्पष्ट लिंग अंतर हैं। वर्ष 1991–1992 में, प्राथमिक शिक्षा में कुल नामांकन 100.9 मिलियन था। 2015–2016 तक कुल नामांकन 129.1 मिलियन तक बढ़ गया था। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन में एकरूपता नहीं थी। वर्ष 2011–2012 (139.9 मिलियन) के लिए उच्चतम नामांकन दर्ज किया गया था , जबकि सबसे कम वर्ष 1993–1994 (97.0 मिलियन) के लिए दर्ज किया गया था।

प्राथमिक शिक्षा के छात्र नामांकन में लिंग अंतर की आरेखीय प्रस्तुतिः

आरेखों का एक महान दृश्य प्रभाव और समझने में आसान होगा और इसलिए आरेखों के माध्यम से संख्यात्मक डेटा प्रस्तुत करना भी उचित माना जाता है। प्राथमिक शिक्षा में छात्रों की संख्या में लिंग भिन्नताओं और असमानताओं को ग्राफ 1 और ग्राफ 2 के माध्यम से व्याकरणिक रूप से समझाया गया है।

ग्राफ-1. भारत में प्राथमिक शिक्षा में लिंग अंतर (लाइन ग्राफ)

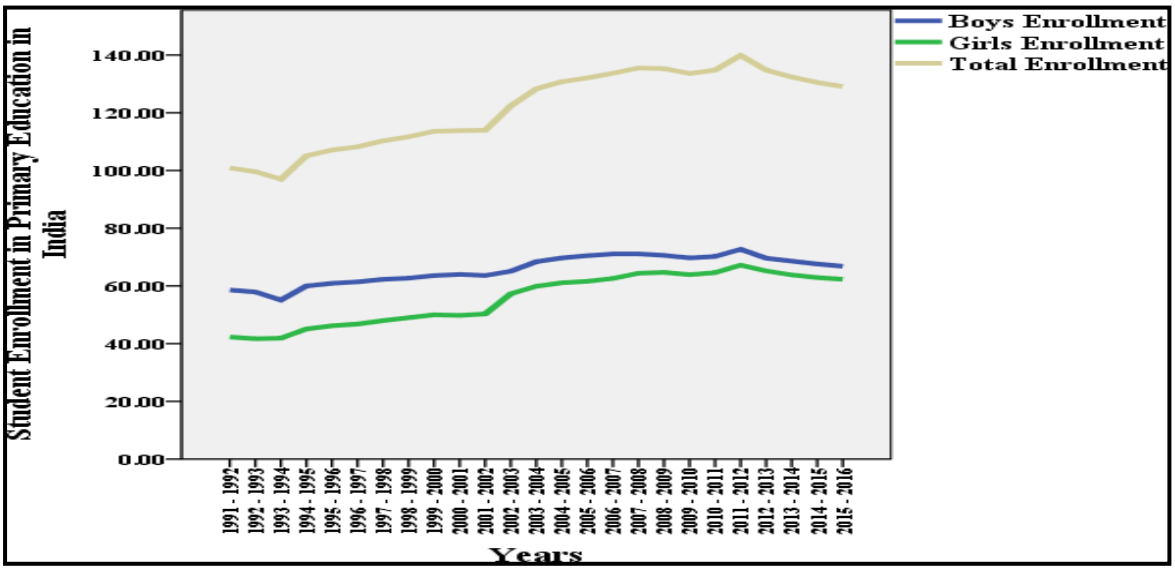

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11Issue 01, January- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|

ग्राफ .2 भारत में प्राथमिक शिक्षा में लिंग अंतर (बार ग्राफ)(लाखों में छात्र नामांकन)

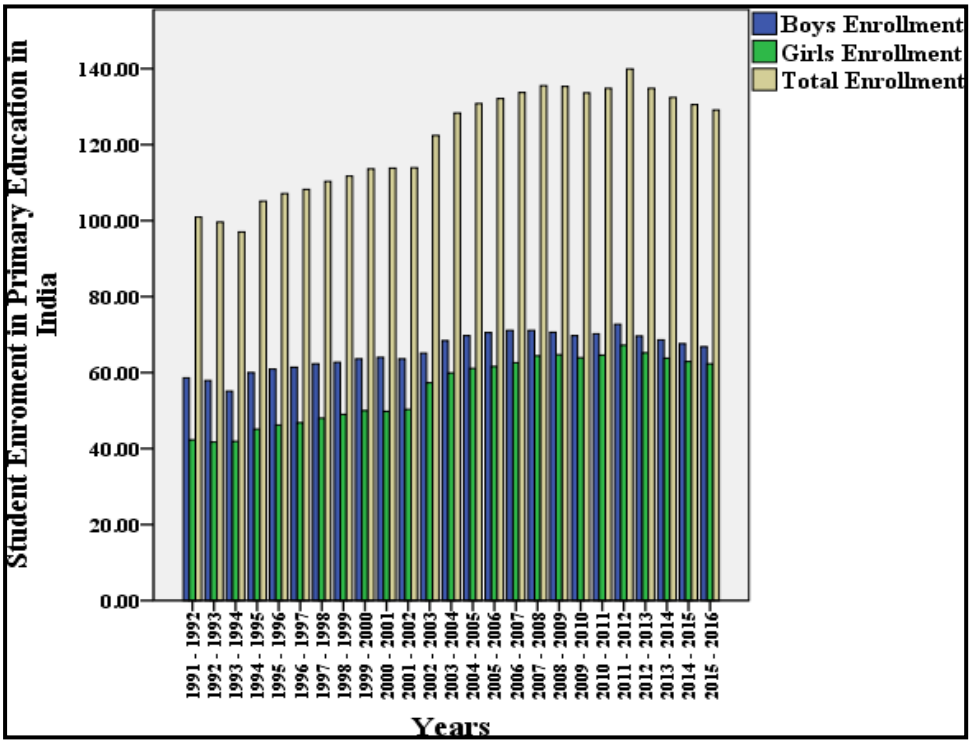

ग्राफ 1. और ग्राफ 2 से यह देखा जा सकता है कि अध्ययन के तहत अवधि के दौरान लड़कों का नामांकन लड़को के नामांकन की तुलना में अधिक है ।

सारांशः

भारत में प्राथमिक शिक्षा के नामांकन में लड़कों और लड़कियों के बीच स्पष्ट लिंग अंतर हैं । वर्ष 1991–1992 में, लड़की का नामांकन केवल था 42.3 मिलियन जबकि लड़के का नामांकन 58.6 मिलियन था। और 2015–2016 तक प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 62.3 मिलियन था जबकि लड़के का नामांकन बढ़कर 66.8 मिलियन हो गया था। प्रतिशत के संदर्भ में, 1991–1992 में लड़की का नामांकन केवल 42 था, जबकि लड़के का नामांकन लगभग 58 था और 2015–2016 तक लड़कियों का नामांकनलगभग 48 था जबकि लड़के का नामांकन हिस्सा घटकर लगभग 52 हो गया है। फिर भी, अध्ययन के तहत 25 साल की अवधि में लिंग अंतर मामूली बदलाव आया है। वर्तमान

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11Issue 01, January- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|

अध्ययन में भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर नीतियों, योजनाओं, समितियों और आयोगों के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया गया है। और भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के रुझानों का विश्लेषण करना। और भारत में शिक्षा के वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए । अध्ययन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे छात्रों के नामांकन, शिक्षकों के रोजगार और स्कूलों की संख्या की जांच करके किया जाता है। और इस अध्ययन में पांच वर्ष की योजना–वार आवंटन, शिक्षा पर व्यय और शिक्षा पर राज्यों और केंद्र के व्यय का हिस्सा शामिल है।

वर्तमान अध्ययन में 25 वर्षों की समय अवधि अर्थात् 1991–1992 से 2015–2016 तक शामिल है , जिसके लिए एक समान और तुलनीय द्वितीयक डेटा उपलब्ध है। तथापि, मानव संसाधन विकास योजना , निगरानी एवं सांख्यिकी मंत्रालय, नई दिल्ली, स्कूल शिक्षा सांख्यिकी, शिक्षा सांख्यिकी, भारत में स्कूल शिक्षा, जिला सूचना मंत्रालय से एकत्र किए गए माध्यमिक आंकड़े शिक्षा प्रणाली , शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण, भारत सरकार। पहले दिए गए उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का उपयोग किया जाता है। अध्ययन सरल उपकरणों जैसे प्रतिशत, वार्षिक वृद्धि दर, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, औसत वार्षिक वृद्धि दर, रैखिक प्रवृत्ति मूल्य, सहसंबंध, भिन्नता का गुणांक, वैरियन ई का विश्लेषण, लिंग समानता सूचकांक, लिंग अंतर, प्रतिशत के साथ किया जाता है लिंग अंतर।

अध्ययन में भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, समितियों और आयोगों के बारे में चर्चा करने की कोशिश की गई अध्ययन में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में छात्रों के नामांकन में रुझानों, प्राथमिक और प्राथमिक में नियोजित शिक्षकों की संख्या में रुझानों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। माध्यमिक स्तर की शिक्षा और इस बारे में जानना कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित कितने स्कूल मौजूद हैं।

अध्ययन में भारत में शिक्षा के वित्तपोषण के बारे में वर्णन करने की कोशिश की गई। इस अध्ययन में पंचवर्षीय योजना–वार आवंटन और शिक्षा पर व्यय के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और शिक्षा पर राज्यों और केंद्र सरकार के व्यय का हिस्सा, और शिक्षा पर राज्य और केंद्रवार जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) प्रतिशत हिस्सदारी को जानना, और भारत में शिक्षा पर योजना और गैर–योजनावार व्यय की पहचान करना।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11Issue 01, January- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|

वार्षिक विकास दर भी सुचारू नहीं है और अध्ययन किया जाता है। उच्च विकास के वर्षों (1994–1995 में 8.35) के साथ–साथ कम या नकारात्मक वृद्धि के वर्ष (2012–2013 में –3.65) हैं। वर्ष 2002–2 003 में लड़कियों के लिए उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर (13.92) दर्ज की गई थी और वर्ष 2012–2013 में उनके लिए सबसे कम (–2.98) दर्ज की गई थी। अनुकूल प्रवृत्ति यह है कि लड़कियों के नामांकन ने लड़कों के लिए 0.55 प्रतिशत और कुल के लिए 1.03 प्रतिशत की तुलना में 1.63 प्रतिशत की उच्चतम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की। लड़कियों के नामांकन में लड़कों के लिए 0.58 प्रतिशत और कुल 1.07 प्रतिशत की तुलना में 1.68 प्रतिशत की उच्चतम औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) दर्ज की गई।

पूर्वगामी विश्लेषण के आधार पर, यह अध्ययन भारत में प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों के सौ प्रतिशत नामांकन को प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रयासों के साथ संयुक्त विशेष नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का सुझाव देता है। और इस प्रकार लीटर एसी के क्षेत्र में लिंग समानता स्थापित करें। और इन कमियों को पाटने के लिए, भारत सरकार को लड़कियों के लिए विशेष साक्षरता अभियान चलाना होगा

संदर्भ ग्रंथ–सूची

1. प्रो डी। पुल्ला राव (2014) "एडुकेशन में मूल्यों को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में महिला सशक्तिकरणः एक ऐतिहासिक विश्लेषण", जर्नल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, वॉल्यूम 20, नंबर 1, अप्रैल, 2014। पीपी 85–93।
2. डॉ. शंजेन्दु नाथ (2014): "भारत में उच्च शिक्षा और महिला भागीदारी" जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज रिसर्च (जेबीएम एंड एसएसआर) आईएसएसएन नंबरः 2319–5614 वॉल्यूम 3, नंबर 2, फरवरी 2014।
3. दरागड़, सायरा बानो एम और वेंकट लक्ष्मी, एच (2014): स्कूली बच्चों के बीच सामाजिक कौशल और व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक । सामाजिक विज्ञान और मानविकी के एशियाई अकादमिक अनुसंधान जर्नल । वॉल्यूम। 1. नहीं। 22. अप्रैल 2014।
4. ऋतिका चंदा पररुक और अरिजीत गोश(2014): "इंडिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम एक अवलोकन" – ब्रिटिश काउंसिल।
5. बलबीर कुमार (2013): "भारत में स्कूल स्तर पर लड़कियों की शिक्षाः अवसर और चुनौतियां" ज्ञान ज्योति ई–जर्नल, खंड 3, अंक 4 (अक्टूबर–दिसंबर 2013) आईएसएसएन 2250–348एक्स

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11Issue 01, January- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|

6. डॉ. जितेंद्रकुमार और सुश्री संगीता (2013): "भारत में महिला शिक्षा की स्थिति" खंड 2, नहीं। 4, अप्रैल 2013, पीपी 162–176।

7. प्रो डी। पुल्ला राव (2013) "लिंग विशिष्ट शैक्षिक नीतियां और कार्यक्रम और फिर भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रभाव", विकास वाणी जर्नल, खंड टप्, अंक 4, अक्टूबर–दिसंबर, 2013।

8. च. पडालू (2012) "भारत में महिला शिक्षा और शिशु और बाल मृत्यु दर – एक अनुभवजन्य विश्लेषण" भारत में स्वास्थ्य विकासः मुद्दे और समाधान, प्रोफेसर डी द्वारा संपादित । पुल्ला राव, मंगलम प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012।

9. प्रो डी। पुल्ला राव (2012) "भारत मे शैक्षिक प्रणाली में लैंगिक असमानता", पीआईआरजेएम, खंड। प्ट, अंक प्, सितंबर, 2012, पीपी 76–87।

10. संपत कुमार (2012): "भारत में शिक्षा में हाल के सुधार – उपलब्धियां और अधूरे कार्य" आईआरजेसी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च वॉल्यूम 1 अंक 8, अगस्त 2012, आईएसएसएन 2277 3630।

11. फरजाना अफरीदी (2010) "भारत में स्कूली शिक्षा में महिलाओं की शक्ति और लिंगों के बीच समानता का लक्ष्य " जनसंख्या अध्ययन, खंड। 64, नहीं। 2 (जुलाई 2010), पीपी। 131–145।

12. पजानकर, विशाल, डी. और पजानकर, प्रणाली, वी. (2010): भारत में स्कूल शिक्षा की स्थिति का विकास । जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज। वॉल्यूम। 22. नहीं। 1. 2010. पी. 15–23.

13. किंगडन, गीता गांधी (2007): भारत में स्कूली शिक्षा की प्रगति। आर्थिक नीति की ऑक्सफोर्ड समीक्षा। वॉल्यूम। 23. नहीं। 2. 2007. पी. 168–195।

14. माइकल वार्ड (2007): "ग्रामीण शिक्षा" भारत अवसंरचना रिपोर्ट 2007, ीजजचः//मकनबंजपवद. दपब.पद/बक50लमंते/ह/न/9थ/वनपअिोजोआई.ोजउ

15. चंद, विजिया शेरी और अमीन – चौधरी, गीता। (2006): " सर्व शिक्षा अभियान (2006) के तहत नवाचार।

16. बंदना पुरकायस्थ, मंगला सुब्रमण्यम, आदि। (2003) "भारत में लिंग का अध्ययनः एक आंशिक समीक्षा" खंड। 17, नहीं। 4 (अगस्त, 2003), पीपी 503–524।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 11Issue 01, January- 2021
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|

17. नंदिनी मांजरेकर (2003): "एक मायावी लक्ष्य की ओर महिलाओं की शिक्षा के लिए समकालीन चुनौतियां?" – आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक 25 अक्टूबर, 2003.पीपी 4577–4582।

18. मैत्रेयी बोर्डिया दास सोनाल्डे देसाई (2003): "शिक्षित महिलाओं को भारत में नियोजित होने की संभावना कम क्यों है? प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं का परीक्षण" – सामाजिक सुरक्षा चर्चा पेपर श्रृंखला संख्या। 0313 – सामाजिक सुरक्षा इकाई मानव विकास नेटवर्क विश्व बैंक।

19. गीता गांधी किंगडन (2002) "महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक–आर्थिक विकास" में प्रकाशित कारण और रहस्योद्घाटनः बाबी और बहाई रेलिगियन में अध्ययन, खंड 13, लॉस एंजिल्सः कलीमत प्रेस, 2002।

20. इला पटेल (1998) "भारत में समकालीन महिला आंदोलन और महिला शिक्षा " शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा / 44, नहीं। 2/3, सामाजिक आंदोलन और शिक्षा (1998), पीपी। 155–175।

।